

**Recommendations for increasing stipend of internee-doctors**

3885. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Director General Health Services has recommended to the Government that the stipend payable to internee-doctors be increased from Rs. 450/- to Rs. 730/- per month; and

(b) if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The Delhi Medical Resident Association has demanded an increase in the rate of stipends. Their demand is receiving attention.

श्री श्री रजिन्द्र लाइब्रेरी के कर्मचारियों का बोनस और भत्ता

3886. श्री चतुर्भुज : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों के वही बोनस, भत्ते आदि देय हैं, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंजूर होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये केन्द्र सरकार की "समूह बीमा योजना और सेवा निवृत्ति पेंशन योजना" अभी तक लागू नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी. के. वर्गन) : (क) दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारी दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड (सेवाएं) उप नियमों में यथा निर्धारित वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों के हकदार हैं। ये उप-नियम उस मूल तथा अनुपुरक नियमावली के आधारे पर बनाए गए हैं जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

इस सम्बन्ध में दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक स्वायत्त निकाय है, इस समय पुस्तकालय के कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के लाभों के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं।

**Seniority of Officers in the Railway Ministry**

3887. SHRI D. P. YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is it a fact that the Ministry of Railways had passed an order dated 4-1-82 depressing the seniority of some officers and that these officers had filed a writ petition against the order in the Delhi High Court;

(b) is it also a fact that the Delhi High Court has not only quashed the said order but also stated in its judgement that the order was passed with a closed and biased mind; and

(c) if so, what action does the Minister for Railways propose to take to ensure that such biased and illegal orders are not passed again?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN-